List of projects for which World Bank assistance was approved till 31st March 1985

(In US $ million)

Name of the Project	Amount of loan/Credit	Utilisation upto 31-3-85	Date of closure of loan/credit
1. M.P. Medium Irrigation . . .	140	39.904	31-3-1987 (6 months extension sought)
2. M.P. Major Irrigation	220	54.48	30-6-1987 (2 years extension sought)
3. Chambal (MP) Irrigation-II . . .	31	10.134	30-6-1987 (year extension sought)
4. M.P. Indira Sarovar (Bodhghat) Hydro-Electric Project-II	300.4*	—	30-6-1992
5. M.P. Urban Development	24.1	0.30	30-6-1989
6. M.P. Agricultural Extension-I . . .	37	94.36	30-6-1987

*This is a new project for which agreement was signed on 1st March, 1985.

Rs. 1000 crores excise duty locked up in Litigation

727. SHRIMATI KRISHNA KAUL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that nearly Rs. 1000 crores excise duty is locked up in litigation in the country; and

(b) if so, what steps Government are taking/have taken to realise the same by ending the litigation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) It is a fact that a large number of cases on central excise matters are under litigation. Most of these cases relate to issues having a bearing on the rate of duty, valuation and excisability of the products. Quantification of revenue involved in individual cases is possible only after Cour decisions are available.

(b) For recovery of arrears, such measures as are considered necessary from time to time continue to be taken. These steps include moving of the various Courts and appellate authorities for early hearing of cases and engaging of eminent lawyers to defend the Government cases.

Abolition of import duty on life saving medical equipments

728. SHRIMATI KRISHNA KAUL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government propose to abolish import duty on life saving medical equipments such as endroscope to provide medical facilities at reasonable cost;

(b) if so, by when; and

(c) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) to (c) Certain specified life-saving drugs, medicines and equipments are exempt from the whole of Customs Duty under Notification No. 208/81-Cus. dated 22nd September, 1981 (as amended). Under this Notification drugs, medicines and equipments not expressly specified therein are also exempt if certified by specified authorities in the Directorate General of Health Services, New Delhi to be life-

saving drugs, medicines or equipments.

There is at present no proposal to declare Endoscopic equipment as "life-saving" for Customs duty exemption purposes.

मारुति कारों की बिक्री में काले धन का प्राप्त होना

729. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व उनके मंत्रालय द्वारा मारुति कारों की बिक्री में प्राप्त होने वाले काले धन के संबंध में की जा रही जांच-पड़ताल पूरी कर ली गयी है, **और**

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) आयकर प्राधिकारी, मूल आवंटितियों द्वारा मारुति वाहनों के लिये किये गये कुछ अन्तरणों की केवल जांच कर रहे थे ताकि इस प्रकार के लेन-देनों में लेखा-बाह्य राशियों के निवेश का पता लगाया जा सके। चूंकि ऐसे मामलों में कर निर्धारण कर-निर्धारण-वर्ष 1985–86 से सम्बन्धित है, इसलिये कर-निर्धारितियों के पास अपनी विवरणियां 31–7–85 तक दाखिल करने का समय है।

मैसर्स मेहर कारपोरेशन तथा अन्य के विरुद्ध मुकदमों का दायर किया जाना

730. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या **वित्त** मंत्री 20 मार्च, 1985 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 947 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स मेहर कारपोरेशन और उसके तीन भागीदारों के खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने बम्बई की अदालत में जो मुकदमें दायर किये थे उनमें कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) सर्वश्री आर० के० जैन और पोद्दारों के जो मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे गये थे, उनकी जांच में हुई प्रगति का विवरण क्या है ; और

(ग) बैंक आफ बड़ौदा, पंजाब एण्ड सिध बैंक, स्टेट बैंक आफ पटियाला द्वारा ऋणदाताओं से ऋण की बकाया राशि वसूल किये जाने के संबंध में कितनी प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने सूचित किया है कि मैसर्स मेहर कारपोरेशन और उसके तीन भागीदारो के खिलाफ 26 जनवरी, 1985 को बंबई के ए० सी० एम० तीसरे न्यायालय में तीन मामलों में तीन अभियोग पत्र दाखिल किये गये थे जिनके मामले में अदालती कार्यवाई चल रही है।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि इन मामलों में जांच अन्तिम चरण में हैं।

(ग) जबकि बैंक आफ बड़ौदा और स्टेट बैंक आफ पटियाला ने सूचित किया है कि मेहर कारपोरेशन के खातों में कोई वसूली नही हुई है, पंजाब एंड सिध बैंक ने मार्च, 1983 में 2,64,874 रुपये की राशि वसूल की थी। बताया जाता है कि सभी तीन बैंकों ने अपनी बकाया रकमों की वसूली के लिये ऋणकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे दायर किये हैं।

महालेखाकार, इलाहाबाद के कार्यालय में चोरी

731. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या **वित्त** मंत्री 14 मई, 1985 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1366 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महालेखाकार, इलाहाबाद के कार्यालय में कथित चोरी के बारे में जो